भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3022
दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय पोषण मिशन की उपलब्धियां

3022. श्री असादुद्दीन ओवैसीः
श्री सयद ईमत्याज ज़लीलः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय पोषण मिशन को स्वीकृति प्रदान की है जिसका लक्ष्य/उद्देश्य कुपोषण कम करने और प्रत्येक वर्ष जन्म के समय कम वजन 2 प्रतिशत तक कम करना है;
(ख) यदि हां, तो फरवरी, 2019 तक प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;
(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मिशन हेतु कुल कितनी निधि आबंटित की गई है;
(घ) क्या सरकार ने देश में उन जिलों को चिह्नित किया है जहां इस मिशन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 2019-20 तक देश में कुल कितने जिलों को इस मिशन के अंतर्गत कवर किया गया है या कवर किए जाने की संभावना है ?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) एवं (ख) : सरकार देश में कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए 18 दिसम्बर, 2017 से पोषण अभियान क्रियान्वित कर रही है । पोषण अभियान का लक्ष्य नीचे दिए गए नियत लक्ष्यों के साथ 2017-18 से शुरू 3 वर्ष की अवधि के दौरान समयबद्ध ढंग से बच्चों (0-6 वर्ष) और गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषणात्मक स्थिति में सुधार हासिल करना है :

क्र.सं.	उद्देश्य	लक्ष्य
1	बच्चों (0-6 वर्ष) में ठिगनेपन का निवारण एवं उसमें कमी लाना	2% प्रतिवर्ष की दर से 6 % तक
2	बच्चों (0-6 वर्ष) में अल्प-पोषण (अल्प वजन की व्याप्तता) का निवारण एवं उसमें कमी लाना	2% प्रतिवर्ष की दर से 6 % तक
3	छोटे बच्चों (6-59 माह) में रक्ताल्पता की व्याप्तता में कमी लाना	3% प्रतिवर्ष की दर से 9 % तक
4	15-49 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं एवं किशोरियों में रक्ताल्पता की व्याप्तता में कमी लाना	3% प्रतिवर्ष की दर से 9 % तक
5	जन्म के समय अल्प वजन (एलबीडब्ल्यू) में कमी लाना	2% प्रतिवर्ष की दर से 6 % तक

पोषण अभियान के परिणामों के बारे में जानकारी इसकी अनुमोदित अवधि के पूर्ण हो जाने के बाद प्राप्त हो सकती है । तथापि, इस बीच यूनीसेफ द्वारा आयोजित व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण (सीएनएनएस) की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में ठिगनेपन, विकास अवरूद्धता एवं अल्पवज़न की दर क्रमश: 34.7%, 17% और 33.4% है, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 में यथा-सूचित स्तरों में सुधार एवं कमी को दर्शाता है ।

(ग) : पोषण अभियान के तहत वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 में क्रमश: 950.00 करोड़ रूपए, 3061.30 करोड़ रूपए और 3400.00 करोड़ रूपए है ।

(घ) एवं (ड़) : देश के सभी जिले पोषण अभियान के तहत शामिल हैं ।

*****